considered for promotion as they have not completed the requisite minimum service required. The question of considering *ad-hoc* appointees, who are not regular in Grade IV, for promotion to Grade III does not, therefore, arise. However, efforts are being made to fill the Grade II vacancies as quickly as possible on a regular basis.

Statement

S. No.	Ministry/Department	No. of posts lying vacant
1.	Ministry of works and Housing.	1
2.	Department of Mines	1
3.	Department of Revenue.	1
4.	Department of Industrial Development	1
5.	Planning Commission;	2
6.	Department of Statistics.	4
7.	Ministry of Home Affairs	1
8.	Ministry of Irrigation	3
9.	Ministry of Rural Development	1
10.	Department of Agrivulture & Cooperation;	1
	Total	16

Regularisation of Grade IV officers in Indian Statistical Service

2094. SHRI DIGAMBAR SINGH: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether there is utter stagnation in Grade IV of the Indian Statistical Service and persons who have put in more than 10 years service in *ad-hoc* basis are still awaiting regularisation; and

(b) if so, when they are likely to be regularised?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS AND DEPARTMENT OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI P. VENKATASUBBAIAH): (a) There is no stagnation in Grade IV of the Indian Statistical Service. A large number of posts in Grade IV of the Service are being held on a purely ad-hoc basis pending regular arrangements being made in accordance with the ISS Rules.

(b) A Select List for promotion of feeder post holders to Grade IV of the Indian Statistical Service against the promotion quota vacancies is under preparation in consultation with the UPSC and is expected to be ready shortly. Such of the *ad-hoc* appointees who are included in this Select List will be appointed to Grade IV of the Service on a regular basis.

कल्पनी नदी के दूषित जल को साफ करने के लिये उठाये गये कदम

†2095. **श्री लक्ष्मण वर्मा : क्या इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश में बेलाडीला लौह इस्पात परियोजना की कोयला खानों "डिपाजिट" संख्या 14, 15 और 11-ग से गन्दे और दूषित पानी के बहाव को रोकने के लिए कितने "टेमिंग" बांधों का निर्माण किया गया और शकनदी

के दूषित जल को साफ करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ;

(ख) क्या यह सच है कि सकनी नदी के किनारे पर बसे लोग नदी के जल के दूषित होने के कारण तपेदिक, प्लेग, मलेरिया आदि रोगों के प्राय: शिकार हो रहे हैं ; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार क्या कदम उठा रही है ?

उद्योग तथा इस्पात और खान मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री चरणजीत चानना): (क) प्री-प्रोसेसिंग संयंत्र में उत्पादित सलाइस (अयस्क के चूरे के पंक) को एकत्र करने के लिए बैलाडिला लौह-अयस्क निक्षेप नं0 5 में एक पछोड़न बांध का निर्माण किया गया है । प्राकृतिक जल-निकास से केवल साफ पानी ही जाने दिया जाता है । यद्यपि सरकार ने बैलाडिला के लौह-अयस्क के निक्षेप नं0–14 के लिए इसी प्रकार के बांध के निर्माण की अनुमति वर्ष 1978 में दी थी तथापि भूमि-अर्जन सम्बन्धी समस्याओं के कारण इस बांध का निर्माण नहीं किया जा सका । इस बारे में मध्य प्रदेश की सरकार से मदद मांगी गई है । निक्षेप नं0 14 के एक भाग के रूप में निक्षेप नं0 11 सी का अभी विकास किया जाना है ।

(ख) और (ग) सरकार के पास ऐसी कोई जानकारी नहीं है जिससे यह पता चलता हो कि शकनी नदी के किनारे पर बसे लोग जल के दूषित होने के कारण रोगों के प्रायः शिकार हो रहे हैं । फिर भी ग्रामवासियों के लिए पीने के लिए साफ पानी की व्यवस्था करने के लिए नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कारपोरेशन ने ग्रामों में प्राकृतिक जल-निकास के साथ-साथ नलकपों और चार पारम्परिक कुओं का निर्माण किया है ।

कागज नियंत्रण आदेश में संशोधन

2096. **श्री रामावतार शास्त्री :** क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कागज नियंत्रण आदेश में संशोधन करने का निर्णय किया है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

उद्योग तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

Employment to displaced persons whose land has been acquired for Vizag Steel Plant

2097. SHRI SUBHASH CHANDRA BOSE ALLURI: Will the Minister of STEEL AND MINES be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Government have decided to provide employment to the displaced persons whose land has been acquired for the sake of Vizag Steel Plant; and

(b) if so, the number of displaced persons who have been provided jobs so far?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY AND STEEL AND MINES (SHRI CHARANJIT CHANANA): (a) and (b). It is the policy of the Government of India to provide employment in the steel plants to one able-bodied person from each family, displaced on account of acquisition of land for construction of the steel plant. Accordingly, Vizag Steel Plant project authorities have been giving preference to displaced persons